

सम्पूर्ण-संक्षिप्त-समर्थ

CURRENT AFFAIRS गुरु

UPSC/State PSC परीक्षा की तैयारी करने वाले हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए



30th AUGUST 2022



FOR DAILY FREE CURRENT AFFAIRS
Follow Our Youtube Channel

 Guru Deekshaa Hindi



INDEX

DAILY CURRENT AFFAIRS NOTES

30th August 2022

1. - जंगल की आग के बारे में:	3
(i) के बारे में:	3
(ii) जंगल की आग के लिए भारत की क्षमता:	3
(iii) जंगल में आग लगने के कारण:	3
(iv) जंगल की आग के परिणाम:	4
(v) वन क्यों महत्वपूर्ण हैं:	4
(vi) जंगल की आग से बचने के प्रयास :	4
2. - पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण:	5
(i) पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र क्या हैं?	5
(ii) उद्देश्य:	5
(iii) महत्व:	5
(iv) इको-सेंसिटिव जोन को किन बाधाओं को दूर करना होगा?	6
(v) कैसे आगे बढ़ा जाए:	6
3. - नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में:	7
(i) एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की परिभाषा है:	7
(ii) एनपीए का एक उदाहरण:	7
(iii) एनपीए के संभावित कारण क्या हो सकते हैं?	7
(iv) एनपीए क्या परिणाम देते हैं?	8
(v) एनपीए से निपटने के लिए किन रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है?	8
(vi) 1993 के डीआरटी (ऋण वसूली न्यायाधिकरण):	9
(vii) 2000 का क्रेडिट सूचना ब्यूरो:	9
(viii) 2001 की लोक अदालतें:	9
(ix) 2002 का सरफेसी अधिनियम:	9



(x)	2005 में कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन:.....	9
(xi)	मिशन इंड्रधनुष 2015:	10
(xii)	2015 में सामरिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर):	10
(xiii)	दिवालियापन और दिवाला संहिता 2016:	10
(xiv)	2017 में, सार्वजनिक एआरसी के खिलाफ निजी एआरसी:	10
4.	- भारत के रक्षा निर्यात का विवरण:	11
(i)	वहां कौन से प्रमुख बिंदु हैं?	11
(ii)	भारत के रक्षा निर्यात कैसे कर रहे हैं?	11
(iii)	रक्षा संबंधी कौन से कार्यक्रम मौजूद हैं?	12
	संपादकीय विश्लेषण	13
1.	मौद्रिक नीति समिति का विवरण:	13
(i)	के बारे में:	13
(ii)	कार्य:	13
(iii)	एमपीसी की संरचना:	13
(iv)	सदस्यों और शर्तों का चयन:	13
(v)	निर्णय कैसे किए जाते हैं?	13
(vi)	क्या है आरबीआई की मौद्रिक नीति?	13
(vii)	मौद्रिक नीति किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है?	14
(viii)	मौद्रिक नीति के उपकरण कैसे प्रबंधित किए जाते हैं?	14
2.	सिविल सेवाओं में आवश्यक सुधार:	15
(i)	भारतीय सिविल सेवाओं का विकास:	15
(ii)	भारतीय सिविल सेवा के मुद्दे:	15
(iii)	नियम आधारित नौकरशाही:	15
(iv)	क्या किया जाना चाहिए यह है:	16
(v)	भर्ती:	16
(vi)	प्रशिक्षण:	17
(vii)	मूल्यांकन:	17
(viii)	ई-पहल:	17



1. - जंगल की आग के बारे में:

जीएस III

विषय→पर्यावरण संरक्षण

के बारे में:

- किसी भी अनियंत्रित और अनियंत्रित दहन या पौधों को जलाने से जो उपलब्ध ईंधन की खपत करता है और पर्यावरणीय कारकों के आधार पर फैलता है, प्राकृतिक संदर्भ में जंगल की आग के रूप में जाना जाता है, जैसे कि जंगल, घास का मैदान, ब्रश भूमि, या टुंड्रा। इसके अन्य नामों में धधकती, जंगल की आग और घास की आग (जैसे, हवा, स्थलाकृति) शामिल हैं।
- जंगल की आग मानवीय गतिविधियों से शुरू हो सकती है जैसे विकास के लिए भूमि को साफ करना, लंबे समय तक सूखा, या दुर्लभ मामलों में, बिजली।
- एक जंगल की आग को जलने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता होती है: ईंधन, ऑक्सीजन और गर्मी।

जंगल की आग के लिए भारत की क्षमता:

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के अनुसार, देहरादून की भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 (ISFR) के अनुसार, 2019 तक, देश के भौगोलिक क्षेत्र के 21.67 प्रतिशत (7,12,249 वर्ग किमी) से अधिक को वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- पेड़ अब 2.89 प्रतिशत अधिक भूमि को कवर करते हैं (95,027 वर्ग किमी)।
- ऐतिहासिक आग की घटनाओं और आंकड़ों के अनुसार, पूर्वोत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों में जंगल जंगल की आग की चपेट में हैं।

- असम, मिजोरम और त्रिपुरा में वनाच्छादित क्षेत्रों को "विशेष रूप से प्रवण" के रूप में देखा गया है।
- आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश को "बहुत अधिक प्रवण" माना जाता है। कई राज्यों में महत्वपूर्ण जंगली क्षेत्र पाए जा सकते हैं।
- MoEFCC की 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, मध्य ओडिशा के साथ, सभी "अत्यंत संभावित" जंगल की आग के हॉटस्पॉट में विकसित हो रहे हैं।
- "बहुत प्रवण" या "मध्यम प्रवण" क्षेत्रों के रूप में, 1,72,374 वर्ग किलोमीटर, या पूरे वन क्षेत्र का लगभग 26.2 प्रतिशत, इन श्रेणियों में आते हैं।

जंगल में आग लगने के कारण:

- भारत में अधिकांश बड़ी आग मानव गतिविधियों का परिणाम है, इस तथ्य के बावजूद कि जंगल की आग के कई विविध प्राकृतिक कारण हैं।
- हाल के अध्ययनों ने जलवायु परिवर्तन को आग में वृद्धि से जोड़ा है, विशेष रूप से विनाशकारी अमेज़न जंगल की आग जिसने पिछले दो वर्षों के दौरान ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है।
- जलवायु परिवर्तन और आग की तीव्रता, लंबाई, आवृत्ति और अत्यधिक ज्वलनशील प्रकृति के बीच एक संबंध है।
- भारत में, जंगल की आग मार्च और अप्रैल के महीनों में सबसे अधिक बार रिपोर्ट की जाती है क्योंकि वहां सूखे लकड़ी, लॉग, मृत पत्ते, स्टंप, सूखी घास और खरपतवार की बहुतायत होती है जो आसानी से एक चिंगारी से जलती हैं।



- उत्तराखंड में एक अन्य प्रमुख मुद्दा शुष्क मिट्टी है। 2019 और 2020 के मॉनसून सीज़न में बारिश देखी गई जो कि मौसमी औसत से क्रमशः 18 और 20% कम थी।
- ज्यादातर आग व्यक्तियों द्वारा शुरू की जाती है, कभी-कभी जानबूझकर भी। यह सामान्य ज्ञान है कि ओडिशा में किसानों ने, जो पिछले महीने सिमलीपाल के जंगल में भीषण आग का सामना किया था, महुआ के फूलों को इकट्ठा करने के लिए सूखे पत्तों में आग लगा दी थी, जिसका उपयोग स्थानीय पेय बनाने के लिए किया जाता है।

जंगल की आग के परिणाम:

- जंगल की आग का मिट्टी, पेड़ की वृद्धि, वनस्पति और समग्र वनस्पतियों और जीवों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- एक आग कई हेक्टेयर जंगल को जला सकती है, और जो राख छोड़ती है वह किसी भी वनस्पति को दोबारा उगने से रोकती है।
- आग की गर्मी जानवरों के आवास को नष्ट कर देती है।
- मिट्टी के घटक भिन्न होने पर मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाती है।
- इसके अतिरिक्त प्रभावित मिट्टी की नमी और उर्वरता हैं।
- वनों का आकार घट सकता है।
- आग से बचने वाले पेड़ आमतौर पर विकास को काफी कम कर देते हैं।

वन क्यों महत्वपूर्ण हैं:

- वन धीमा होने और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने दोनों के लिए आवश्यक हैं।

- वे कार्बन के जलाशय, सिंक और आपूर्तिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।
- एक स्वस्थ वन में किसी भी अन्य स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की तुलना में अधिक कार्बन का भंडारण और पृथक्करण करने की क्षमता होती है।
- भारत में, जहां 1.70 लाख गांव जंगल के पास स्थित हैं, बहुत से लोग अपने अस्तित्व (जनगणना 2011) के लिए ईंधन की लकड़ी, बांस, चारे और थोड़ी मात्रा में लकड़ी पर निर्भर हैं।

जंगल की आग से बचने के प्रयास :

- वास्तविक समय में जंगल की आग पर नज़र रखने के लिए, FSI (भारतीय वन सर्वेक्षण) ने 2004 में फ़ॉरेस्ट फ़ायर अलर्ट सिस्टम विकसित किया।
- सिस्टम का अद्यतन संस्करण, जो जनवरी 2019 में सुलभ हो गया, अब नासा और इसरो से प्राप्त उपग्रह डेटा का उपयोग करता है।
- जंगल की आग और जंगल की आग रोकथाम और प्रबंधन योजना (एनएपीएफएफ) पर 2018 की राष्ट्रीय कार्य योजना।
- स्रोत→ डाउन टू अर्थ पत्रिका



2. - पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों का विवरण:

जीएस III

विषय→पर्यावरण संरक्षण

पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र क्या हैं?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की राष्ट्रीय पशु कार्य योजना (2002-2016) में राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाओं के 10 किलोमीटर के भीतर भूमि को पर्यावरण-नाजुक क्षेत्रों या पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के रूप में नामित करने की आवश्यकता है। वन्यजीव अभयारण्य। 1986 के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम द्वारा इसकी आवश्यकता थी। (MoEFCC)।

उद्देश्य:

- प्राकृतिक परिदृश्य के लिए एक प्रकार के "सदमे अवशोषक" के रूप में सेवा करने के लिए, ईएसजेड राष्ट्रीय उद्यानों, जंगलों और वन्यजीव अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों के आसपास बनाए गए हैं।
- उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों और कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों के बीच, ये क्षेत्र संक्रमण के रूप में कार्य करेंगे।
- वाणिज्यिक लकड़ी का उपयोग, औद्योगिक खनन, चीरघर, ऐसे व्यवसाय जो पर्याप्त मात्रा में HEPs का उत्पादन करते हैं, और व्यवसाय जो प्रदूषक पैदा करते हैं, सभी निषिद्ध हैं।

- एक राष्ट्रीय उद्यान में गर्म हवा के गुब्बारे, अपशिष्ट या अन्य ठोस अपशिष्ट का निर्वहन, या खतरनाक सामग्री का उत्पादन पर्यटन से संबंधित गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं।
- पेड़ों को काटना, होटलों और रिसॉर्ट्स का निर्माण करना, व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्राकृतिक पानी का दोहन करना, बिजली की लाइनें लगाना, भारी गियर, कीटनाशकों आदि के उपयोग के माध्यम से कृषि को काफी हद तक बदलना और नई सड़कों का निर्माण करना सभी गतिविधियाँ हैं जो विनियमन के अधीन हैं।
- नियमित बागवानी या कृषि अभ्यास, हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का दोहन और जैविक खेती जैसी गतिविधियों की अनुमति है।

महत्व:

- विकास गतिविधियों के हानिकारक प्रभावों को कम किया जाता है।
- शहरीकरण और अन्य विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए, संरक्षित क्षेत्रों के करीब के क्षेत्रों को इको-सेंसिटिव जोन के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- इन-सीटू संरक्षण अपने मूल वातावरण में खतरे में पड़ी प्रजातियों के संरक्षण को संदर्भित करता है। इसका एक उदाहरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण है।
- लॉगिंग और मानव-पशु संघर्ष की मात्रा को कम करें।
- पारिस्थितिक क्षेत्र मानव-पशु संघर्ष को कम करते हैं और वनों के विनाश को रोकते हैं।
- प्रबंधन की मूल और बफर रणनीति, जो पड़ोसी समुदायों को भी लाभ और सुरक्षा प्रदान करती है, संरक्षित क्षेत्रों के विकास के आधार के रूप में कार्य करती है।



इको-सेंसिटिव जोन को किन बाधाओं को दूर करना होगा?

- विकास परियोजनाएं: ऐसी गतिविधियां जिनमें ईएसजेड में निर्माण शामिल है, जैसे कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सड़कों, बांधों और अन्य प्रकार के बुनियादी ढांचे का निर्माण, पारिस्थितिकी तंत्र के साथ बातचीत करना, इसे नुकसान पहुंचाना और प्राकृतिक व्यवस्था को बिगाड़ना।
- नए नियम और नीतियां:
- 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 1972 का पशु संरक्षण अधिनियम, दोनों ही वन्य जीवों के अवैध शिकार को हतोत्साहित करने के लिए कुछ नहीं करते, वन लोगों के अधिकारों की अवहेलना करते हैं। यह ESZ की विकास पहलों का समर्थन करने के लिए किया जाता है।
- पर्यटन: पर्यावरण पर्यटन की बढ़ती मांग को समायोजित करने के लिए, वनों की कटाई, समुदायों के निष्कासन आदि के माध्यम से पार्कों और अभयारण्यों के आसपास की भूमि को छीन लिया जा रहा है।
- एक विदेशी प्रजाति का परिचय बबूल और क्युलरिस और नीलगिरी के बागान, दूसरों के बीच, क्षेत्र के मूल जंगलों पर दबाव डाल रहे हैं।
- ESZ में, जलवायु परिवर्तन का भूमि, जल और पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जैव विविधता और पारिस्थितिकी को असम की बाढ़ और बार-बार होने वाली जंगल की आग के परिणामस्वरूप बहुत नुकसान हुआ है।
- स्थानीय समुदाय: संरक्षित क्षेत्रों पर कुछ दबावों में खेती के तरीकों में बदलाव, बढ़ती आबादी और जलाऊ लकड़ी और अन्य वन उत्पादों की मांग में वृद्धि शामिल है।

कैसे आगे बढ़ा जाए:

- प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिए राज्यों को एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए ताकि दीर्घकालिक सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- सरकार को अपनी भूमिका को आर्थिक बूस्टर की भूमिका तक सीमित करके राज्य के भाग्य को जल्दी से नहीं बढ़ाना चाहिए।
- कार्बन फुटप्रिंट्स को बढ़ावा देना, खराब हुए जंगलों की मरम्मत करना और विलुप्त हो रहे आवासों को वापस लाना संभव है।
- संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना और संसाधनों के अति प्रयोग के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित करना।

• स्रोत → डाउन टू अर्थ पत्रिका



3. - नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में:

जीएस III

विषय → अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे

एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) की परिभाषा है:

- आपने देखा होगा कि बैंक की संपत्ति में से एक को उसका ऋण माना जाता है। नतीजतन, एक परिसंपत्ति को एक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति माना जाएगा यदि ऋण के सिद्धांत, ब्याज, या दोनों घटकों को ऋणदाता (एक बैंक) (एनपीए) को वापस भुगतान नहीं किया जा रहा था।
- कोई भी परिसंपत्ति जो अपने निवेशकों को निश्चित अवधि के लिए रिटर्न देना बंद कर देती है, उसे गैर-निष्पादित (एनपीए) माना जाता है।
- अधिकांश देशों में और कई उधार देने वाले संगठनों के बीच यह अवधि सामान्य रूप से 90 दिनों की होती है। उधारकर्ता और वित्तीय संस्थान जिन नियमों और परिस्थितियों पर सहमत होते हैं, वे अलग-अलग हो सकते हैं, क्योंकि वे एक परिभाषित मानक नहीं हैं।

एनपीए का एक उदाहरण:

- आइए कल्पना करें कि एक व्यवसाय को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) द्वारा रु. 10 करोड़ (जैसे: किंगफिशर एयरलाइंस)। 10% वार्षिक की सहमत ब्याज दर के बारे में सोचें। आइए मान लें कि शुरू में सब कुछ बिना किसी रोक-टोक के आगे बढ़ा और एयरलाइन उद्योग को बाजार की ताकतों का समर्थन मिला, जिससे किंगफिशर को इस

वजह से ब्याज का भुगतान करने की अनुमति मिली। आइए कल्पना करें कि बाद में, किसी भी कारण से - प्रशासनिक, तकनीकी या कॉर्पोरेट - कंपनी 90 दिनों के लिए ब्याज दरों का भुगतान करने में असमर्थ है। इस वजह से, किंगफिशर एयरलाइंस को दिया गया ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में लेबल किए जाने के लिए एक अच्छा उम्मीदवार है।

एनपीए के संभावित कारण क्या हो सकते हैं?

- छायादार या असंबंधित व्यवसायों में नकद निवेश करना।
- विनियामक पर्यावरण परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसायों को होने वाली हानियाँ।
- विशेष रूप से सरकारी ऋण माफी कार्यक्रमों के बाद मनोबल कम है।
- वैश्विक, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय वित्तीय संकटों के परिणामस्वरूप कंपनियों का लाभ मार्जिन अनुबंध, उनकी बैलेंस शीट पर दबाव डालता है और अंततः उन्हें ऋण और ब्याज भुगतान का भुगतान करने से रोकता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की सामान्य मंदी, जैसे 2011 के बाद भारत के मामले में, जिसके कारण एनपीए अधिक तेजी से बढ़ रहा था (उदाहरण के लिए, 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट)।
- एक विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के परिणामस्वरूप वहां के व्यवसाय प्रभावित होते हैं, और कुछ विफल भी हो सकते हैं।
- एनपीए उन ऋणों का परिणाम है जिन्हें पहले सस्ते दरों पर स्वीकार किया गया था, लेकिन बाद में उच्च दरों पर सेवा दी गई, साथ ही उछाल की अवधि के दौरान अनियोजित कॉर्पोरेट हाउस विस्तार।



- कार्यस्थल में खराब प्रबंधन के कारण, जिसमें जानबूझकर अक्षमता और चूककर्ता शामिल हैं।
- खराब शासन और नीतिगत पक्षाघात के कारण ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) बन जाते हैं, जो परियोजनाओं की समयसीमा और प्रगति की दर को धीमा कर देते हैं। एक उदाहरण के रूप में बुनियादी ढांचा क्षेत्र का उपयोग करना।
- किसी दिए गए वाणिज्यिक उद्योग में भयंकर प्रतिस्पर्धा। एक उदाहरण के रूप में भारत में दूरसंचार क्षेत्र पर विचार करें।
- सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय कारकों के कारण भूमि अधिग्रहण में देरी हो रही है।
- एक बेईमान उधार रणनीति जिसमें गुप्त ऋण लेनदेन शामिल हैं।
- भूकंप, सूनामी, बीमारी का प्रकोप, बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण।
- डंपिंग से सस्ते आयात होते हैं, जिससे घरेलू कंपनियों को नुकसान होता है। भारत में इस्पात उद्योग पर विचार करें।

- लाभकारी पहलों से प्रतिकूल पहलों के लिए धन को स्थानांतरित करना।
- यह संभव है कि स्थिर निवेश के परिणामस्वरूप बेरोजगारी हुई हो।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खराब प्रदर्शन से शेयरधारक रिटर्न कम हो जाता है, जिससे भारत सरकार को दिए जाने वाले लाभांश की मात्रा कम हो जाती है। नतीजतन, यह सामाजिक और ढांचागत विकास के लिए धन के वितरण को धीमा कर सकता है, जिसका नकारात्मक सामाजिक और राजनीतिक असर होगा।
- निवेशकों को उचित पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं।
- भारतीय विशेषताओं के साथ बैलेंस शीट सिंड्रोम द्वारा निवेश-आधारित विकास रुका हुआ है, जो बैंकिंग और कॉर्पोरेट दोनों क्षेत्रों में तनावग्रस्त बैलेंस शीट की विशेषता है।
- एनपीए से जुड़े मामले न्यायपालिका के पहले से ही भारी केसलोड पर अधिक दबाव डालते हैं।

एनपीए क्या परिणाम देते हैं?

- उधारदाताओं के लिए लाभ मार्जिन कम हो गया है।
- बैंकिंग क्षेत्र में तनाव अन्य परियोजनाओं को निधि देने के लिए उपलब्ध धन की मात्रा को कम करता है, जिसका संपूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- बैंकों ने अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई हैं।

एनपीए से निपटने के लिए किन रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है?

- भारत सरकार ने न्यायिक, वित्तीय और नीतिगत वातावरण में सुधार के लिए कई प्रयास किए हैं। हालांकि, एनपीए के साथ भारत का अनुभव हाल का नहीं है। एनपीए को संबोधित करने के लिए, नरसिम्हम समिति ने 1991 में कई सुधार सुझाव जारी किए। उनमें से कुछ का उपयोग वास्तविक स्थितियों में किया गया था।



1993 के डीआरटी (ऋण वसूली न्यायाधिकरण):

- केस-समाधान प्रक्रिया को तेज करने के लिए। वे 1993 के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कारण ऋण की वसूली अधिनियम द्वारा कवर किए गए हैं। हालांकि, उनमें से पर्याप्त नहीं हैं, इस प्रकार कई क्षेत्रों में मामले अक्सर दो से तीन साल से अधिक समय तक चलते हैं।

2000 का क्रेडिट सूचना ब्यूरो:

- ऋण को गलत हाथों में पड़ने से बचाने के लिए एक अच्छी सूचना प्रणाली की आवश्यकता होती है, जिसके परिणामस्वरूप एनपीए होता है। यह विशेष रूप से चूककर्ताओं और विलफुल डिफॉल्टरों के बारे में जानकारी बनाए रखने और प्रसारित करके बैंकों की मदद करता है।

2001 की लोक अदालतें:

- वे छोटे ऋणों को संभालने और पुनर्प्राप्त करने में सहायक होते हैं, लेकिन 2001 में प्रकाशित आरबीआई मानकों के तहत केवल 5 लाख रुपये तक के ऋण के लिए अनुमति दी जाती है। वे सहायक होते हैं क्योंकि परिणामस्वरूप कम मामले अदालतों के सामने लाए जाते हैं।

2002 का सरफेसी अधिनियम:

- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम 2002 यह अधिनियम बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को अपनी गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) की वसूली के लिए अदालत की मदद के बिना सुरक्षित संपत्ति खरीदने और

बेचने की अनुमति देता है। रुपये के बकाया मूल्य के साथ एनपीए खाते। 1 लाख या अधिक। बैंकों को पहले नोटिस पोस्ट करना आवश्यक है। फिर, इस घटना में कि उधारकर्ता चूक करता है, वे कर सकते हैं:

2005 में कॉर्पोरेट ऋण पुनर्गठन:

- यह भुगतान की गई दरों को कम करके और कंपनी को दायित्व चुकाने में लगने वाले समय को बढ़ाकर व्यवसाय पर ऋण के बोझ को कम करने का प्रयास करता है।

5:25 नियम - 2014:

- इन्फ्रास्ट्रक्चर और कोर इंडस्ट्रीज के लिए दीर्घकालिक परियोजना ऋणों की लचीली संरचना के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि परियोजना की समय-सारणी लंबी होती है और उन्हें अपनी पुस्तकों में एक बड़े समय के लिए पैसा वापस नहीं मिलता है, यह सुझाव दिया गया था कि हर 5-7 साल में ऋण और ऐसे उद्यमों के नकदी प्रवाह की रक्षा के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं के लिए पुनर्वित्त की आवश्यकता है।

संयुक्त ऋणदाता फोरम 2014:

- यह दबावग्रस्त ऋण वाले सभी पीएसबी को शामिल करके लाया गया था। यह कई बैंकों से एक ही व्यक्ति या कंपनी के पास जाने से ऋण को रोकने के लिए मौजूद है। यह उन उदाहरणों को रोकने के लिए स्थापित किया गया था जिनमें कोई व्यक्ति एक बैंक से पैसे उधार लेता है और फिर उसे दूसरे को उधार देता है।



मिशन इंद्रधनुष 2015:

- पीएसबी को बदलने के लिए इंद्रधनुष ढांचा एबीसीडीईएफजी द्वारा पीएसबी के आधुनिकीकरण और उनके सामान्य प्रदर्शन में सुधार के लिए लागू की गई सबसे महत्वपूर्ण सुधार परियोजना रही है क्योंकि 1970 में बैंकिंग का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

2015 में सामरिक ऋण पुनर्गठन (एसडीआर):

- इस विचार के अनुसार, जिन बैंकों ने कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं को पैसा उधार दिया है, उनके पास उस पैसे के सभी या एक हिस्से को कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी में बदलने का विकल्प है, जिसे उन्होंने इसे उधार दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों को जरूरत पड़ने पर स्वामित्व में बदलाव शुरू करने के लिए बेहतर क्षमता देना और यह सुनिश्चित करना है कि दबावग्रस्त खातों की वसूली में प्रमोटरों का बड़ा हिस्सा हो।

2017 में, सार्वजनिक एआरसी के खिलाफ निजी एआरसी:

2017 के बुरे बैंक:

- आर्थिक सर्वेक्षण 16-17 में एक अन्य विषय पर प्रकाश डाला गया है जो एक खराब बैंक की स्थापना है जो सभी दबावग्रस्त ऋणों को लेगा और अनुकूलनीय नियमों और विधियों के अनुसार उनका प्रबंधन करेगा। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अपनी बैलेंस शीट का प्रबंधन करना आसान बना देगा, जिससे वे अधिक विकास पहलों को निधि देने और नए लॉन्च करने में सक्षम होंगे।

- स्रोत → द इकोनॉमिक टाइम्स

दिवालियापन और दिवाला संहिता 2016:

- इसे भारत में बाहर निकलने की पहली के चक्रव्यूह चुनौती (आर्थिक सर्वेक्षण) के जवाब में विकसित किया गया था। इस कानून का उद्देश्य कॉर्पोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों और व्यक्तियों के पुनर्गठन और दिवाला समाधान से संबंधित कानूनों को समयबद्ध तरीके से और अधिकतम करने के लिए सभी हितधारकों के हितों के बीच उद्यमशीलता, ऋण उपलब्धता और संतुलन को प्रोत्साहित करना है। ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति का मूल्यांकन।



4. - भारत के रक्षा निर्यात का विवरण:

जीएस III

विषय→आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

वहां कौन से प्रमुख बिंदु हैं?

- निर्यात सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के 20% और निजी क्षेत्र की कंपनियों के 70% द्वारा किया गया था।
- अर्थव्यवस्था का 90% हिस्सा निजी क्षेत्र में हुआ करता था, लेकिन अब अधिक सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन सशस्त्र बलों में शामिल हैं।
- भारतीय उद्यम उत्तरोत्तर अमेरिकी रक्षा निगमों की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बन रहे हैं, इस तथ्य के बावजूद कि हाल के वर्षों में अमेरिका से भारत के रक्षा उपकरणों के आयात में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है।
- रक्षा वस्तुओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए हाल ही में क्या पहल की गई है?
- भारत और फिलीपींस ने जनवरी 2022 में तट-आधारित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तीन बैटरियों की बिक्री के लिए 374.96 मिलियन अमरीकी डालर में एक समझौता किया।
- पिछले दो वर्षों में, भारत ने लगातार 310 विभिन्न हथियारों और प्रणालियों के आयात को गैरकानूनी घोषित कर दिया, जिससे निर्यात में वृद्धि हुई।
- अगले पांच से छह वर्षों में, इन हथियारों और प्रणालियों का घरेलू स्तर पर बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाएगा।

- निजी क्षेत्र की बेहतर समझ से रक्षा निर्यात में तेज वृद्धि हुई है।

भारत के रक्षा निर्यात कैसे कर रहे हैं?

- रक्षा घटकों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की सरकार की योजना में प्रमुख घटक के रूप में रक्षा निर्यात शामिल है।
- इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्रांस, नेपाल, मॉरीशस, श्रीलंका, इजराइल, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, स्पेन और चिली कुछ ऐसे देश हैं। कि 30 से अधिक भारतीय रक्षा निगमों ने हथियार और उपकरण भेज दिए हैं।
- एवियोनिक्स पैकेज, रेडियो और रडार सिस्टम, अपतटीय गश्ती नौकाएं, इंजीनियरिंग उपकरण, अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ निर्यात हैं।
- इस बीच, भारत का रक्षा निर्यात अनुमानों से कम होता जा रहा है।
- 2015 और 2019 के बीच, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भारत को हथियारों के 23वें सबसे बड़े निर्यातक (SIPRI) के रूप में वर्गीकृत किया।
- फिर भी, भारत दुनिया के हथियारों के निर्यात में केवल 0.17 प्रतिशत का योगदान देता है।
- निर्यात को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय के भीतर एक विशिष्ट संगठन की कमी के कारण, भारत के रक्षा निर्यात का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है।
- भारत को 2024 तक 5 अरब डॉलर मूल्य के रक्षा उत्पादों का निर्यात करने की उम्मीद है।



रक्षा संबंधी कौन से कार्यक्रम मौजूद हैं?

DPEPP 2020 (रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति):

- DPEPP 2020 देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं के लिए एक व्यापक सड़क योजना के रूप में कार्य करने के लिए है, जो उन्हें निर्यात और स्वतंत्रता के लिए एक केंद्रित, संगठित और प्रमुख अभियान प्रदान करता है।
- निजी क्षेत्र को अधिक शक्ति देना परिवर्तनों का उद्देश्य है।
- भारतीय आईडीडीएम (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित) डीपीपी 2016 के लिए एक बिल्कुल नई श्रेणी है। यदि कोई भारतीय फर्म इसे चुनती है, तो भारतीय आईडीडीएम को अन्य सभी श्रेणियों पर वरीयता प्राप्त होती है।

सामरिक सहयोग:

- एक रणनीतिक साझेदारी दृष्टिकोण के माध्यम से, भारतीय उद्यम प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, भारत में निर्माण और उत्पादन करने की क्षमता और भारत में उन परियोजनाओं को बनाए रखने की क्षमता प्राप्त करने के लिए विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) के साथ काम कर सकते हैं।
- वर्तमान में उपयोग में पहली पारंपरिक पनडुब्बी RFP है।
- **स्रोत→ प्रेस सूचना ब्यूरो**



संपादकीय विश्लेषण

सदस्यों और शर्तों का चयन:

1. मौद्रिक नीति समिति का विवरण:

के बारे में:

- भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 को वित्त अधिनियम (भारत), 2016 द्वारा एमपीसी बनाने के लिए संशोधित किया गया था।
- इसे रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर और नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) सहित उपकरणों का उपयोग करके मौद्रिक नीति स्थापित करने का काम सौंपा गया है।
- यह भारत की केंद्र सरकार द्वारा 1934 में संशोधित RBI अधिनियम की धारा 45ZB के अनुपालन में बनाया गया था।

कार्य:

- एमपीसी एमएसएफ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट सुविधा सहित विभिन्न नीतिगत दरों के चयन के लिए जिम्मेदार है।

- चयन: कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज-सह-चयन समिति एमपीसी के लिए आरबीआई गवर्नर, आर्थिक मामलों के सचिव और अर्थशास्त्र, बैंकिंग, वित्त और मौद्रिक नीति के क्षेत्र में तीन विशेषज्ञों के साथ मिलकर सरकारी उम्मीदवारों का चयन करेगी।
- एमपीसी के सदस्यों को चार साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है और वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं।

निर्णय कैसे किए जाते हैं?

- बहुमत से निर्णय लिए जाते हैं, प्रत्येक सदस्य के पास एक मत होता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। बराबरी की स्थिति में राज्यपाल का निर्णायक मत होगा; हालाँकि, उसके पास अन्य पैनलिस्टों द्वारा लिए गए निर्णयों को रद्द करने की शक्ति नहीं होगी।

एमपीसी की संरचना:

- कमेटी में छह लोग होंगे। छह में से तीन सदस्यों का प्रस्ताव सरकार करेगी। एमपीसी द्वारा स्वीकार किए गए निर्वाचित अधिकारियों के लिए कोई नामांकन नहीं होगा।
- अन्य तीन सदस्य आरबीआई से होंगे, और गवर्नर पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। सदस्यों में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, जो मौद्रिक नीति के प्रभारी हैं, साथ ही साथ केंद्रीय बैंक के कार्यकारी निदेशक भी शामिल होंगे।

क्या है आरबीआई की मौद्रिक नीति?

- भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की "मौद्रिक नीति" से तात्पर्य है कि यह कैसे मौद्रिक संसाधनों का उपयोग करता है जो जीडीपी बढ़ाने और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपने नियंत्रण में हैं।
- 1934 का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम आरबीआई को मौद्रिक नीति पर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करता है।



मौद्रिक नीति किन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहती है?

- चक्रवर्ती समिति की सिफारिशों के अनुसार, भारत की मौद्रिक नीति को नए वित्तीय संस्थानों के निर्माण के साथ-साथ आर्थिक विकास, इक्विटी और सामाजिक न्याय का समर्थन करना चाहिए।
- जबकि भारत सरकार का लक्ष्य देश की जीडीपी विकास दर में तेजी लाना है, आरबीआई लगातार मुद्रास्फीति को एक प्रबंधनीय सीमा के भीतर कम करने का प्रयास कर रहा है।
- देश के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने और इसके मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए, मौद्रिक नीति समिति इष्टतम नीतिगत व्याज दर का चयन करती है।

मौद्रिक नीति के उपकरण कैसे प्रबंधित किए जाते हैं?

- मौद्रिक नीति उपकरण दो श्रेणियों में आते हैं: गुणात्मक साधन और मात्रात्मक साधन।
- मात्रात्मक साधनों की सूची में ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, सीमांत स्थायी सुविधा और तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) शामिल हैं।
- गुणात्मक साधनों के उदाहरण नैतिक अनुनय, प्रत्यक्ष कार्रवाई और मार्जिन संशोधन हैं।



2. सिविल सेवाओं में आवश्यक सुधार:

भारतीय सिविल सेवा के मुद्दे:

भारतीय सिविल सेवाओं का विकास:

- शासक (स्वामी), नौकरशाही (अमात्य), क्षेत्र (जनपद), गढ़वाली राजधानी (दुर्गा), कोषागार (कोसा), सेना (डंडा), और सहयोगी प्रशासनिक संगठन के सात आवश्यक अंग हैं। कौटिल्य (मित्र) के अर्थशास्त्र में उल्लिखित हैं।
- अर्थशास्त्र के अनुसार, उच्च नौकरशाही मंत्रों और अमात्यों से बनी थी। मंत्रिगण उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार के रूप में कार्य करते थे, जबकि अमात्य शाही अधिकारियों के रूप में कार्य करते थे।
- मध्ययुगीन काल: मुगल साम्राज्य के दौरान, मनसबदारी प्रणाली ने प्रशासन के लिए रूपरेखा के रूप में कार्य किया।
- मनसबदारी प्रणाली में सरकारी लोगों का एक समूह शामिल था जिसका उपयोग नागरिक या सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था।
- ब्रिटिश भारत में, 1835 में मैकाले की रिपोर्ट के अनुमोदन के परिणामस्वरूप सिविल सेवाओं में काफी बदलाव देखा गया।
- मैकाले रिपोर्ट ने सिफारिश की कि ब्रिटिश साम्राज्य के हितों को आगे बढ़ाने के लिए केवल सबसे प्रतिभाशाली आवेदकों को भारतीय सिविल सेवा के लिए चुना जाए।
- स्वतंत्रता के बाद, भारतीय सार्वजनिक सेवा प्रणाली ने कई ब्रिटिश लक्षणों को प्रदर्शित करना जारी रखा, जैसे कि एक एकीकृत प्रशासनिक संरचना, अकादमिक उपलब्धि पर आधारित एक ओपन-एंट्री सिस्टम और स्थायी कार्यकाल।

- चूंकि वे जन प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं, इसलिए सिविल अधिकारियों को अनुकूलनीय होना चाहिए। लेकिन यह लगातार दिखाया गया है कि लोग परिवर्तन का विरोध करते हैं क्योंकि वे अपने फायदे और संभावनाओं से ग्रस्त हैं, उन्हें अपने आप में लक्ष्य बना लेते हैं।
- उदाहरण के लिए, संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों का समाज पर काफी प्रभाव पड़ा है। स्थानीय सरकारें आज स्वशासन की संस्थाएँ हैं, चाहे शहरी या ग्रामीण समुदायों में हों।
- सिविल सेवकों के नियंत्रण और जवाबदेही की नई प्रणालियों को स्वीकार करने से इनकार करने के साथ-साथ उनके स्थानांतरण कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के परिणामस्वरूप बांछित दृष्टि अभी तक साकार नहीं हुई है।

नियम आधारित नौकरशाही:

- हमारा अनिवार्य रूप से नियम-पुस्तक नौकरशाही से मतलब था जब हमने कहा कि इसमें जनता की वास्तविक जरूरतों पर विचार किए बिना लिखित नियमों और कानूनों का पालन करना शामिल है।
- नियम-पुस्तिका नौकरशाही के कारण, जो लालफीताशाही, जटिल प्रक्रियाओं, और संगठन जो जनता की जरूरतों का जवाब देने के लिए "नौकरशाही" जैसे मुद्दे पैदा करते हैं, कुछ सरकारी कर्मचारी "नौकरशाही व्यवहार" के रूप में वर्णित मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं।



- राजनीतिक हस्तक्षेप: स्थानीय लोक सेवक नियमित रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ काम करते हैं। दोनों को सामाजिक विकास, कल्याण, कल्याण और शांति को बढ़ावा देकर आम जनता के हितों को आगे बढ़ाना चाहिए।
- जनता की मांग को पूरा करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि का प्रभाव प्रशासनिक कर्मचारियों के व्यवहार पर पड़ता है। इसलिए, एक प्रशासनिक अधिकारी को राजनीतिक गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- कभी-कभी, इस हस्तक्षेप से भ्रष्टाचार और योग्य लोक सेवकों के मनमाने स्थानान्तरण जैसे मुद्दे पैदा हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सबसे योग्य अधिकारियों के परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अक्षमताओं ने भी संगठन को विफलता के जोखिम में डाल दिया।
- संरचना के साथ समस्याएं: सिविल सेवा में कई संरचनात्मक मुद्दे हैं।
- विशेषज्ञ अधिकारी: कानून के शासन को बनाए रखना और कार्यकारी आदेशों का पालन करना राज्य की आवश्यक जिम्मेदारियों में से एक है जिसे पूरा करने के लिए मुख्य रूप से सिविल सेवा जिम्मेदार है।
- हालाँकि, वैश्वीकरण और आर्थिक सुधारों द्वारा लाई गई बदलती जरूरतों के परिणामस्वरूप, राज्य की भूमिका बदल गई है।
- नतीजतन, तकनीकी नवाचार (उदाहरण के लिए साइबर सुरक्षा) के परिणामस्वरूप नई चुनौतियां सामने आई हैं। इसलिए नीतिगत स्तर पर विषय ज्ञान वाले विशेष अधिकारियों की मांग अधिक है।
- यह सुनिश्चित करना कि जवाबदेही और पारदर्शिता है, साथ ही समावेशी और प्रतिनिधि निर्णय लेना, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

- जहां कुछ सरकारी सेवाओं में नौकरी के कई अवसर हैं, वहीं कुछ में कुछ ही हैं।

क्या किया जाना चाहिए यह है:

- इन प्रतिबंधों को दूर करने के लिए शासन, प्रशिक्षण और मूल्यांकन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

भर्ती:

- संघीय और राज्य स्तरों पर दी जाने वाली 60 से अधिक विभिन्न सरकारी सेवाओं को कम करने के लिए सेवाओं के युक्तिकरण और सामंजस्य की आवश्यकता है।
- उम्मीदवारों को एक केंद्रीय प्रतिभा पूल में जोड़ा जाना चाहिए, जो तब उन्हें इस अनुसार असाइन करेगा कि उनकी योग्यता स्थिति की आवश्यकताओं से कितनी अच्छी तरह मेल खाती है।
- पार्श्व प्रवेश को बढ़ावा देना: यदि विशेषज्ञों को काम पर रखा जाता है, तो वे सरकार के उच्च स्तर के लिए बहुत आवश्यक अनुभव प्रदान करेंगे।
- सेवा वितरण की आउटसोर्सिंग: प्रशासनिक बुनियादी ढांचे पर निर्भरता को कम करने के लिए सेवा वितरण आउटसोर्सिंग पहल की जानी चाहिए। सर्वोत्तम आउटसोर्सिंग दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए, आउटसोर्सिंग के लिए संभावित सेवाओं को इंगित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है। कई पीपीपी मॉडल पर गौर किया जाना चाहिए।



प्रशिक्षण:

- जिला-दर-जिला आधार पर चल रहे प्रशिक्षण और विसर्जन कार्यक्रमों को डिजाइन करना आवश्यक है।
- आचार संहिता बनाकर सिविल सेवकों में नैतिक मूल्यों को स्थापित करना आवश्यक है।
- उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने और भविष्य के कार्य निर्धारित करने के लिए मध्य-कैरियर परीक्षा और कौशल मूल्यांकन किया जा सकता है।

मूल्यांकन:

- लोक सेवकों के मूल्यांकन के लिए संस्थागत लक्ष्यों को स्थापित किया जाना चाहिए और लगातार निगरानी की जानी चाहिए। प्रमुख जिम्मेदारी/फोकस क्षेत्रों को स्थापित किया जाना चाहिए, और विवेकाधीन चर को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए।
- ऑनलाइन स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (स्पैरो) टेम्पलेट का उपयोग सभी संघीय और राज्य संवर्गों द्वारा किया जाना चाहिए।
- अप्रभावी अधिकारियों को स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहिए; अधिकारियों के लिए प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करें, और बेंचमार्क को पूरा करने में असमर्थ समझे जाने वाले लोगों को सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर करें।
- वर्तमान प्रोत्साहन कार्यक्रमों की समीक्षा करें और उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचानने के लिए नए शुरू करें।

ई-पहल:

- एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए, संस्थागत भ्रष्टाचार का पता लगाने और रोकथाम के उपायों को मजबूत किया जाना चाहिए। परिणामस्वरूप, वर्तमान सुरक्षा सावधानियों की समीक्षा करना महत्वपूर्ण है।
- केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMs) के निष्पादन को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- ई-ऑफिस की शुरुआत: सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ई-ऑफिस को अपनाने के लिए तत्काल आग्रह किया जा सकता है।
- सेवाओं को शीघ्रता से वितरित करना: प्रशासनिक विलंब को कम करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सक्रिय क्लाइंट इनपुट के लिए चैनल मौजूद हैं, प्रत्येक विभाग को अपनी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने का प्रयास करना चाहिए।

Guru Deekshaa IAS is happy to announce first ever kannada current affairs magazine for kannada medium aspirants of Karnataka. The three important thumb rules for any competitive exam are



Vijay Kumar G

Founder and Director
Guru Deekshaa IAS

-  First-NCERT/STATE syllabus books which helps to develop your understanding on the subjects
-  Second-Daily current affairs helped to build your further understanding of the events related to your examination, Apart from knowledge it build the personality of an individual which brings in confidence to face any examination.
-  Third-Practice previous year question papers and mock test available in the market to train your mind as per the requirement of the examination.

Thousand miles of journey starts with single step, We at Guru Deekshaa have taken this first step towards empowering you to prepare for civil for services. Now its your turn to start preparation and achieve your dream of becoming IAS/IPS.

CALL US FOR MORE DETAILS

 **76 76 74 98 77**

JOIN OFFICIAL TELEGRAM FOR MATERIAL AND UPDATES

 @GURU_DEEKSHAAIAS



FOLLOW OUR INSTAGRAM FOR DAILY UPDATES

 GURUDEEKSHAA

